अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	फ़र्न की नई प्रजाति 'ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी' की खोज
2.	‘100 आइकन्स ऑफ राजस्थान’ इनिशिएटिव
3.	राजस्थान कृषि विभाग का 32 संगठनों के साथ MoU
4.	‘राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स – 2017’ में संशोधन
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (BMVSS) का 2 संस्थानों के साथ MoU 2. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस : जयपुर 3. अरुंधति चौधरी : कॉमनवेल्थ गेम्स - 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व 4. अंडर-23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान 5. राजस्थान में M-PACS की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPI) रैंकिंग 6. डेटा की साइबर सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला 7. राज्य में 240 श्री अन्न आउटलेट्स
6.	विश्व जनसंख्या दिवस
7.	वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)
8.	राष्ट्रीय प्राधिकरण पत्र जारी करने का कार्यक्रम (एलओए)
9.	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
10.	आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA)
11.	भारत-न्यूजीलैंड संबंध
12.	पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (एलआरजीआर)
13.	विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट 2026
14.	वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2026

राजस्थान परिदृश्य

फ़र्न की नई प्रजाति 'ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी' की खोज

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ सीमा क्षेत्र में स्थित मेनाल में फ़र्न की नई प्रजाति की खोज की गई।

मुख्य बिन्दु:

- **नामकरण :** ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी।
- नई प्रजाति का नाम 'ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी' राजस्थान के वरिष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पूर्व कुलपति प्रो. चतुर्भुज गेना के सम्मान में रखा गया है।

- **खोज का श्रेय :** माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. बी.एल. यादव को।
- इस फ़र्न की खोज के बाद राजस्थान में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जिनमें से 8 केवल मेनाल में पाई जाती है।
- फ़र्न के इस पौधे को मिट्टी के कटाव को रोकने और उर्वरता बनाए रखने में सहायक माना जाता है।
- **पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग :** यह एक औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में घाव, सूजन और त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता था।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

Q.1. हाल ही में मेनाल क्षेत्र में खोजी गई नई फर्न प्रजाति का नाम क्या है?

(a) ओफियोग्लोसम मेनालेंसिस

(b) ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी

(c) ओफियोग्लोसम राजस्थानी

(d) ओफियोग्लोसम यादवई

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

'100 आइकन्स ऑफ राजस्थान' इनिशिएटिव

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा '100 आइकन्स ऑफ राजस्थान' पहल की शुरुआत की गई।

मुख्य बिन्दु:

- **पहल का उद्देश्य :** राज्य के 100 ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करना, जिन्होंने अपने नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से राजस्थान के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हो।
- इस पहल के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- चयन प्रक्रिया के तहत 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं तथा 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन किया जाएगा।
- इस पहल के तहत उद्योग, व्यापार, निर्यात, उद्यमिता, स्टार्टअप, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, हस्तशिल्प, महिला उद्यमिता, शिक्षा, सामाजिक उद्यमिता, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने वाले व्यक्ति पात्र होंगे।
- चयनित व्यक्तियों को 'द 100 आइकन्स कम्पेंडियम' में स्थान दिया जाएगा। साथ ही, उनकी उपलब्धियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया जाएगा तथा राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न रणनीतिक संवादों और ज्ञान-विनिमय कार्यक्रमों में सहभागिता का अवसर मिलेगा।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

Q. '100 आइकन्स ऑफ राजस्थान' पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(i) इस पहल की शुरुआत राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा की गई है।

(ii) इसके तहत राजस्थान के विकास में योगदान देने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा।

(iii) चयनित व्यक्तियों में 55 पुरुष और 45 महिलाएँ शामिल होंगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल (i) और (ii)

(b) केवल (ii) और (iii)

(c) केवल (i) और (iii)

(d) (i), (ii) और (iii)

राजस्थान कृषि विभाग का 32 संगठनों के साथ MoU

चर्चा में क्यों?

- प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि नवाचार, आधुनिक तकनीकों के प्रसार तथा किसानों की आय में सतत् वृद्धि के लिए हाल ही में राजस्थान कृषि विभाग द्वारा 32 विभिन्न संगठनों के साथ समझौता-ज्ञापन (MoUs) साइन किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- 32 संगठनों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग (NIAM) सहित 10 एग्रीटेक स्टार्टअप्स तथा 20 सिविल सोसाइटी संगठन (CSOs) शामिल है।
- **महत्त्व :** ये समझौता ज्ञापन (MoUs) राजस्थान में कृषि क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण साबित होंगे।

- **प्रकृति :** सभी समझौता-ज्ञापन गैर-वित्त पोषित (Non-Financial) हैं। इससे राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए विभागीय योजनाओं की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ेगी।
- **प्रमुख क्षेत्र :** इन साझेदारियों के माध्यम से प्राकृतिक एवं जैविक कृषि, जलवायु अनुकूल कृषि, जल संरक्षण, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन, कृषि प्रशिक्षण, क्षमता विकास, कृषि नीति निर्माण, कृषि-2047 रोडमैप, कार्बन क्रेडिट, मूल्य संवर्धन, प्रमाणन, विपणन, महिला किसान सशक्तीकरण तथा जनजातीय क्षेत्रों में कृषि विकास जैसे क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा।
- **एग्री इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल :** विभाग द्वारा कृषि नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'एग्री इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल' की स्थापना की जाएगी।
- इस सेल के अंतर्गत एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जो मार्गदर्शन, समस्या समाधान एवं समन्वय के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा।
- यह सेल कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKS), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), सहकारी संस्थाओं, उद्योग जगत, निवेशकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर स्टार्टअप्स को तकनीकी, संस्थागत एवं व्यावसायिक सहयोग उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **NIAM द्वारा स्टार्टअप्स के लिए वित्तीयन :** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग (NIAM) द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत 25 स्टार्टअप्स को ₹25 लाख तक का, 25 स्टार्टअप्स को ₹5 लाख तक का तथा चार विद्यार्थियों को ₹4 लाख प्रति विद्यार्थी स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है।

- **फार्मर रजिस्ट्री आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली : 25 जून, 2026 को राजस्थान कृषि विभाग द्वारा सिरोही एवं राजसमंद जिलों में 'फार्मर रजिस्ट्री आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली' लागू करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया।**
- **यह पायलट प्रोजेक्ट एग्रीस्टेक (AgriStack) योजना के अंतर्गत जारी फार्मर रजिस्ट्री का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय उर्वरक तंत्र के तहत शुरू किया गया है।**

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

Q. राजस्थान में कृषि क्षेत्र से संबंधित हालिया पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(i) NIAM द्वारा PM-RKVY के अंतर्गत 25 स्टार्टअप्स को ₹25 लाख तक का अनुदान दिया जाता है।

(ii) चार विद्यार्थियों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए ₹4 लाख प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है।

(iii) फार्मर रजिस्ट्री आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट सिरोही और राजसमंद जिलों में शुरू किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल (i) और (ii)

(b) केवल (ii) और (iii)

(c) केवल (i), (iii) और (iv)

(d) (i), (ii) और (iii)

‘राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स – 2017’ में संशोधन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान सरकार द्वारा 'राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम' (RMMCR-2017) में संशोधन किए गए।

मुख्य बिन्दु:

- **नए संशोधनों का उद्देश्य :** खनन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, पर्यावरण अनुकूल और व्यावहारिक बनाना। साथ ही, न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश से बंद खदानों के पट्टाधारकों को राहत देना।
- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 के तहत अब खनन पट्टों और क्वारी लाइसेंसों के बीच ‘गैप एरिया' का आवंटन ई-नीलामी से किया जाएगा।
- साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और सतत् खनन को बढ़ावा देने के लिए सभी खनन पट्टाधारकों के लिए कम से कम 3 स्टार रेटिंग हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित अवधि में रेटिंग प्राप्त नहीं करने पर खदान का संचालन निलंबित किया जा सकता है।
- निर्धारित समय पर स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट जमा नहीं करने पर ₹500 प्रतिमाह (अधिकतम ₹5,000) तक जुर्माना लगाया जाएगा।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML)

- **स्थापना :** वर्ष 1974
- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राजस्थान सरकार के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन के लिए जिम्मेदार है।
- **कंपनी का मुख्य उद्देश्य :** खनिजों के खनन में लागत प्रभावी तकनीकी नवाचारों को अपनाना और खनिज आधारित डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में विविधता लाना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

✂️ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (BMVSS) का 2 संस्थानों के साथ MoU** ■ 'जयपुर फुट' निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (BMVSS) ने हाल ही में विकलांगों और दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण एवं पुनर्वास की दिशा में दो महत्त्वपूर्ण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। 1. दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश। 2. डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। ■ **MoU का मुख्य उद्देश्य :** उत्तर प्रदेश में रहने वाले विकलांग और दिव्यांग व्यक्तियों को शारीरिक तथा सामाजिक रूप से पुनर्वासित करना।
2.	**सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस : जयपुर** ■ राजस्थान बजट 2025-26 के तहत, जयपुर में ₹60 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना की जा रही है। ■ यह केंद्र मुख्य रूप से खनन के वैज्ञानिक और सतत् विकास, अनुसंधान (R&D) और खनिजों की सटीक मैपिंग के लिए कार्य करेगा। **Q. राजस्थान में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स' की स्थापना कहाँ की जा रही है?** (a) उदयपुर (b) जोधपुर (c) जयपुर (d) कोटा
3.	**अरुंधति चौधरी : कॉमनवेल्थ गेम्स - 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व** ■ कोटा निवासी अरुंधति चौधरी ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स - 2026 में मुक्केबाजी (बॉक्सिंग) स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ■ **भार वर्ग :** 70 किलोग्राम महिला वर्ग। ■ अरुंधति राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) के लिए चयनित होने वाली राजस्थान की पहली मुक्केबाज हैं।

	2026 राष्ट्रमंडल खेल : ■ **आयोजन :** 23 जुलाई से 2 अगस्त, 2026 तक। ■ **आयोजन स्थल :** स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। **Q. अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में किस भार वर्ग की मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी?** (a) 60 किलोग्राम महिला वर्ग (b) 65 किलोग्राम महिला वर्ग (c) 70 किलोग्राम महिला वर्ग (d) 75 किलोग्राम महिला वर्ग
4.	**अंडर-23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान** ■ **आयोजन :** रोहतक (हरियाणा)। ■ **राजस्थान का प्रदर्शन :** एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य सहित कुल चार पदक। ■ 113 अंकों के साथ राजस्थान ने पहली बार टीम चैंपियनशिप में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ■ **स्वर्ण पदक विजेता :** 68 किलोग्राम भार वर्ग में अश्विनी विश्नोई।
5.	**राजस्थान में M-PACS की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPI) रैंकिंग** ■ भारत सरकार द्वारा निर्धारित की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPI) के आधार पर राजस्थान की एम-पैक्स (M-PACS) की हर महीने रैंकिंग जारी की जाती है। **जून माह की रैंकिंग:** ■ **प्रथम स्थान :** नीमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति (डीडवाना-कुचामन)। (77.50 अंक) ■ **द्वितीय स्थान :** भीया ग्राम सेवा सहकारी समिति (बूँदी) (76.50 अंक) ■ **तृतीय स्थान :** घाट का बराना ग्राम सेवा सहकारी समिति (बूँदी) (74 अंक) ■ **मल्टीपरपज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (M-PACS) :** प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति गठन की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राजस्थान में 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

6.	**डेटा की साइबर सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला** ■ **आयोजक :** सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) के सहयोग से। ■ **मुख्य विषय :** "Strengthening Cybersecurity Frameworks for State Data" (राज्य के डेटा के लिए साइबर सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करना)। ■ **स्थान :** सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस (COERRA), जयपुर।
7.	**राज्य में 240 श्री अन्न आउटलेट्स** ■ राज्य सरकार द्वारा 'श्री अन्न' पहल के तहत प्रदेश में 240 श्री अन्न आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं, जिनसे पोषण के साथ ही स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है। ■ इन आउटलेट्स का मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्पादित होने वाले मोटे अनाजों (जैसे बाजरा, ज्वार, रागी आदि), जिन्हें अब 'श्री अन्न' का नाम दिया गया है, और उनसे बने स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है। **Q. 'श्री अन्न' पहल के तहत राजस्थान में कितने श्री अन्न आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं?** (a) 120 (b) 180 (c) 240 (d) 300

भूगोल एवं भू-विज्ञान

विश्व जनसंख्या दिवस

चर्चा में क्यों?

- विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को वैश्विक जनसंख्या के मुद्दों और उनके सामाजिक, आर्थिक तथा विकासात्मक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।

मुख्य बिन्दु:

- **उत्पत्ति:** विश्व जनसंख्या दिवस की उत्पत्ति 11 जुलाई, 1987 से हुई है, जब वैश्विक जनसंख्या लगभग पाँच अरब तक पहुँच गई, जिसने तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि और इसके परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया।
- **स्थापना:** जनसंख्या-संबंधी चुनौतियों पर बढ़ती चिंताओं की प्रतिक्रिया में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 1989 में औपचारिक रूप से विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की।
- **उद्देश्य:** यह दिवस मातृ स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोज़गारी, आर्थिक कठिनाई, प्रवासन और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच जैसी जनसंख्या-संबंधी चुनौतियों पर चर्चा को प्रोत्साहित करता है।
- **थीम 2026:** वर्ष 2026 की थीम है "युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना – वर्तमान तथा भविष्य के लिये", जो संबंधों, माता-पितृत्व एवं पारिवारिक जीवन के संबंध में युवाओं के विकल्पों को समझने एवं समर्थन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

UTKARSH CLASSES CIVIL SERVICES

- **रिपोर्ट:** यह थीम लाइव्स, चॉइसेज एंड फ्यूचर्स: व्हाट यंग पीपल वांट एंड व्हाट शेप्स देयर डिसीजंस अबाउट रिलेशनशिप्स एंड पेरेंटहुड रिपोर्ट पर आधारित है।
- **जनसंख्या प्रवृत्ति:** वैश्विक जनसंख्या को एक अरब तक पहुँचने में हज़ारों वर्ष लगे, लेकिन अगली दो शताब्दियों में सात गुना तक विस्तार हुआ। यह वर्ष 2011 में सात अरब तक पहुँच गई और वर्ष 2030 तक लगभग 8.5 अरब और वर्ष 2050 तक 9.7 अरब तक पहुँचने का अनुमान है।
- **भारत की जनसंख्या प्रवृत्ति:** भारत (1.4 अरब) दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक बना हुआ है, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2060–2080 के दशक तक भारत की जनसंख्या के लगभग 1.7–1.9 अरब के आस-पास चरम पर पहुँचने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके स्थिर होने या धीरे-धीरे घटने की संभावना है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

आर्थिक घटनाक्रम

वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की विश्व निवेश रिपोर्ट, 2026 के अनुसार, भारत दो स्थान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करने वाला 11वाँ सबसे बड़ा देश बन गया है, जिसमें 2025 में निवेश प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्य बिन्दु:

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रदर्शन

- भारत ने 2025 में 38.89 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया, जो 2024 के 27.09 बिलियन डॉलर की तुलना में 44% की वृद्धि दर्शाता है ।
- **भारत में ग्रीनफील्ड निवेश:** घोषित ग्रीनफील्ड निवेश का मूल्य 2024 में 111.14 बिलियन डॉलर से घटकर 2025 में 74.12 बिलियन डॉलर हो गया।
- हालांकि, भारत ने 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी घोषित ग्रीनफील्ड निवेश परियोजना को आकर्षित किया। अमेरिका स्थित अल्फाबेट इंक ने भारत में एक डेटा सेंटर में 14.5 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की, जिससे वह वैश्विक सूची में शीर्ष पर पहुंच गया।

MCQ:

Q. हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर 'विश्व निवेश रिपोर्ट, 2026' निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई है?

(A) विश्व आर्थिक मंच (WEF)

(B) संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD)

(C) विश्व बैंक (World Bank)

(D) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

योजनाएँ एवं नीतियाँ

राष्ट्रीय प्राधिकरण पत्र जारी करने का कार्यक्रम (एलओए)

चर्चा में क्यों?

- उपराष्ट्रपति ने खुले समुद्रों में मत्स्य पालन के सतत् दोहन के लिए प्राधिकरण पत्र (एलओए) जारी करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्य बिन्दु:

- यह पहल भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और खुले समुद्रों में संसाधनों के सतत् दोहन के लिए एक अनुकूल ढाँचा तैयार करने की केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा को क्रियान्वित करती है।
- खुले समुद्र में मत्स्य पालन से तात्पर्य उन समुद्री संसाधनों से है जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के क्षेत्रों से परे जलक्षेत्र में वितरित होते हैं ।

राष्ट्रीय प्राधिकरण पत्र जारी करने का कार्यक्रम (एलओए)

- **एलओए:** भारतीय ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों को खुले समुद्र में संचालन करने के लिए अनिवार्य, पोत-विशिष्ट, गैर-हस्तांतरणीय प्राधिकरण, जो 3 वर्षों के लिए वैध होता है।
- भारतीय ध्वज वाले मत्स्यन पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य पालन के सतत् दोहन के लिए दिशानिर्देश, 2025 के तहत यह अनिवार्य है।
- **डिजिटलीकरण:** पारदर्शी प्रक्रिया और अनुपालन के लिए ReALCraft पोर्टल (मत्स्य पालन नौकाओं का पंजीकरण और लाइसेंसिंग) के साथ एकीकृत ।
- **प्राथमिकता:** मत्स्य पालन सहकारी समितियों, मछली किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) और भारतीय मछुआरों को।
- **जिम्मेदार और टिकाऊ मत्स्य पालन:** क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों द्वारा निर्धारित संरक्षण उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

संबंधित समाचार: ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन (2026-2036) शुरू किया गया

- ओडिशा को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री निर्यात के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रमुख ब्लू इकोनॉमी पहल।
- यह आधुनिक मत्स्य पालन अवसंरचना, वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन और बाजार संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि मछली उत्पादन, रोजगार, मछुआरों की आय और टिकाऊ समुद्री मत्स्य पालन विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)

चर्चा में क्यों?

- कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत (स्थापना के बाद से) भारत भर में व्यक्तिगत किसानों को 9,404 करोड़ रुपये मूल्य की 21.61 लाख कृषि मशीनें वितरित की गई हैं।

मुख्य बिन्दु:

- 27,554 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 25,608 एफएमबी और 646 हाई-टेक हब स्थापित किए गए; 40,918 हेक्टेयर क्षेत्र में 40,928 ड्रोन प्रदर्शन किए गए।

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)

- **मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- **लॉन्च:** 2014-15
- **प्रकार:** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना
- **उद्देश्य:** उत्पादकता बढ़ाने, श्रम की मेहनत कम करने और खेती की लागत घटाने के लिए समावेशी कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएँ

- **वित्तीय सहायता:** डीबीटी के माध्यम से कृषि मशीनरी के लिए सब्सिडी (सामान्य किसानों के लिए 40%; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 50%)।
- वित्तीय सहायता के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी), कृषि मशीनरी बैंक (एफएमबी) और हाई-टेक उपकरण हब की स्थापना ।
- प्रशिक्षण, परीक्षण, प्रदर्शन, फसल कटाई के बाद मशीनीकरण और फसल अवशेष प्रबंधन।
- **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र:** छोटी मशीनरी के लिए 100% तक सब्सिडी और महिला एवं मध्यम आकार की मशीनरी (एफएमबी) के लिए 95% तक सहायता के साथ बेहतर समर्थन।
- 30% धनराशि महिला किसानों के लिए आवंटित की गई है।

- किसान ड्रोन को बढ़ावा देता है (आईसीएआर, केवीके और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 10 लाख रुपये प्रति ड्रोन तक; एफपीओ के लिए 75% अनुदान)।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

- **लॉन्च:** वर्ष 2007
- **मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना; आरकेवीवाई-राफ्तार (2017-18) के रूप में पुनर्गठित।
- **उद्देश्य:** सार्वजनिक निवेश, उत्पादकता, बुनियादी ढाँचे और किसानों की आय बढ़ाकर समग्र कृषि विकास को बढ़ावा देना।
- यह यंत्रीकरण, मूल्यवर्धन, नवाचार, कृषि स्टार्टअप और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA)

चर्चा में क्यों?

- भारत ने वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में 13वीं आसियान-भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति और संबंधित उप-समिति की बैठकों की मेजबानी की।

मुख्य बिन्दु:

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA)

- आसियान-भारत व्यापार समझौता (AITIGA) भारत और दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के बीच हस्ताक्षरित एक व्यापक, बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।
- यह व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रित करने वाला एक कानूनी और शुल्क ढाँचा स्थापित करता है, जिससे क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों पर आयात शुल्क कम किया जा सके ।
- **हस्ताक्षर और प्रवर्तन:** प्रारंभिक समझौते पर 13 अगस्त, 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2010 को लागू हुआ था ।
- **मेजबान स्थल:** वाणिज्य भवन, नई दिल्ली, भारत, हाइब्रिड प्रारूप में चल रहा है।
- **सहभागिता:** इसमें आसियान के सभी 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे : ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।

उद्देश्य:

- अधिक संतुलित और टिकाऊ व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए व्यापार संहिता को फिर से लिखना और विषम टैरिफ संरचनाओं का सामना करने वाले घरेलू भारतीय निर्माताओं की चिंताओं को सीधे संबोधित करना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

भारत-न्यूजीलैंड संबंध

चर्चा में क्यों?

- न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्य बिन्दु:

वैश्विक भूराजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन

- न्यूजीलैंड ने मौजूदा वैश्विक स्थिति को एक "महत्त्वपूर्ण मोड़" के रूप में वर्णित किया है, जहां दुनिया नियमों पर आधारित प्रणाली से शक्ति पर आधारित प्रणाली की ओर और मुख्य रूप से बहुपक्षीय ढाँचे से अधिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है।
- न्यूजीलैंड के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की नियम-आधारित व्यवस्था से छोटे देशों को लाभ हुआ है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि अंतरराष्ट्रीय नियम छोटे और बड़े दोनों देशों पर समान रूप से लागू होते हैं।
- उन्होंने रक्षा, सुरक्षा और जन-जन संबंधों को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों के तीन स्तंभों के रूप में भी रेखांकित किया।

भारत-न्यूजीलैंड संबंध

- **राजनयिक संबंध:** भारत और न्यूजीलैंड ने 1952 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। दोनों देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन सिद्धांतों को साझा करते हैं।
- न्यूजीलैंड ने 2011 में अधिसूचित अपनी 'भारत के लिए द्वार खोलना' नीति में भारत को एक प्राथमिकता वाले देश के रूप में पहचाना था, जिसे 2015 में दोहराया गया था ।
- **आर्थिक सहयोग:** वर्तमान में, न्यूजीलैंड ओशिनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- 2024 में, न्यूजीलैंड का आयात 47 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि निर्यात 42 अरब अमेरिकी डॉलर था।
- **सेवा व्यापार:** भारत से न्यूजीलैंड को सेवाओं का निर्यात 2024 में 13% बढ़कर 634 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। प्रमुख क्षेत्रों में यात्रा, आईटी और व्यावसायिक सेवाएँ शामिल हैं।

- 2024-25 में, भारत से न्यूजीलैंड को होने वाला निर्यात न्यूजीलैंड से होने वाले आयात से अधिक था, जिससे देश के साथ सकारात्मक व्यापार संतुलन बना रहा।
- भारत और न्यूजीलैंड ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (आईएन-एनजेड एफटीए) पर हस्ताक्षर किए।

- **सीमा शुल्क सहयोग:** 2024 में, न्यूजीलैंड और भारत ने व्यापार संबंधों को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग को तेज करने के उद्देश्य से एक सीमा शुल्क सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **प्रवासी:** न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के 292,092 व्यक्ति हैं।
  - o न्यूजीलैंड में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत है, जो आईटी, हॉस्पिटैलिटी, विज्ञान, इंजीनियरिंग और वास्तुकला जैसे विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
  - o न्यूजीलैंड में हिंदी पाँचवीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
- **रक्षा सहयोग:** 2025 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन ने द्विपक्षीय रक्षा जुड़ाव के लिए एक औपचारिक संस्थागत ढाँचा प्रदान किया।
- भारत-न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता का उद्घाटन वर्ष 2025 में नई दिल्ली में हुआ था ।

MODEL QUESTION:

Q. नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था (Rules-based international order) से छोटे देशों को क्या प्राथमिक लाभ होता है?

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

विज्ञान प्रौद्योगिकी

पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (एलआरजीआर)

चर्चा में क्यों?

- डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (एलआरजीआर) का सफल उड़ान परीक्षण किया।

मुख्य बिन्दु:

पिनाका

- पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम (एमबीआरएल) है, जिसका नाम भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर रखा गया है ।
- इसे रूसी मूल की ग्रैड रॉकेट प्रणाली के प्रतिस्थापन के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया था।
- इस प्रणाली का सर्वप्रथम परिचालन उपयोग कारगिल युद्ध (1999) के दौरान किया गया था ।

विशेषताऐं

- एक सर्व-मौसम रॉकेट प्रणाली जिसकी मारक क्षमता लगभग 120 किलोमीटर है, जो मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेटों का एक साथ दागने में सक्षम है ।
- इसे शूट-एंड-स्कूट क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है , जिससे दुश्मन के जवाबी हमलों से बचने के लिए गोलीबारी के बाद तेजी से स्थान बदला जा सकता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट, 2026

चर्चा में क्यों?

- विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट, 2026 वैश्विक नवाचार के महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करती है, जिसमें दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमूर्त निवेश में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्य बिन्दु:

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) और इटली के लुईस बिजनेस स्कूल (LBS) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित।
- **मूर्त निवेश:** भौतिक संपत्तियों पर किया गया खर्च, जैसे कारखाने, मशीनरी, भवन आदि।
- **अमूर्त निवेश:** अनुसंधान एवं विकास, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, संगठनात्मक जानकारी, ब्रांड, डिजाइन और बौद्धिक संपदा (आईपी) जैसी गैर-भौतिक संपत्तियों पर किया गया व्यय।
- **महत्त्व:** यह नवाचार, उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता, ब्रांड मूल्य और दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- कुल अमूर्त निवेश में अमेरिका अग्रणी है; तीव्रता के मामले में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है।
- **परिसंपत्ति रुझान:**
  - o भारत में सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणी हैं
  - o वैश्विक स्तर पर, संगठनात्मक पूँजी और अनुसंधान एवं विकास

MCQ:

Q. हाल ही में चर्चा में रही 'विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट, 2026' निम्नलिखित में से किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है?

(A) विश्व आर्थिक मंच (WEF) और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय
(B) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) और लुईस बिजनेस स्कूल (LBS)
(C) विश्व बैंक और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल
(D) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और नीति आयोग

वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक, 2026

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, 2026 जारी किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** यह सूचकांक विश्वभर के शहरों में जीवन स्थितियों का मूल्यांकन करता है, और शहरी जीवनयोग्यता, लचीलापन और जीवन की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक मानदंड के रूप में कार्य करता है।
- **प्रकाशक:** इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू)।
- **कवरेज:** 30 से अधिक गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों का उपयोग करके 173 शहरों का आकलन किया गया।
- **स्कोरिंग:** 5 मापदंडों पर 1-100 के पैमाने पर - स्थिरता (25%), स्वास्थ्य सेवा (20%), संस्कृति और पर्यावरण (25%), शिक्षा (10%), और अवसंरचना (20%)।
- **मुख्य निष्कर्ष**
  - o **विश्व के शीर्ष शहर:** कोपेनहेगन, वियना, मेलबर्न।
  - o **भारत:** नई दिल्ली (120), मुंबई (121), चेन्नई (123), बेंगलुरु (127)।

MCQ:

Q. हाल ही में चर्चा में रहा 'वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक, 2026' (Global Liveability Index) निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है?

(A) विश्व आर्थिक मंच (WEF)

(B) इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU)

(C) संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम (UN-Habitat)

(D) विश्व बैंक

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213